ब्लाक के लिए स्वयं अथवा अपने सहयोगियों आदि के साथ ऑफर जमा कर सकता हैं।

(ख) ऑफर जमा करने हेतु निम्नलिखित पात्रता निर्धारित की गई हैं :-

1. ऑफरकर्ता को हीरों के पूर्वेक्षण, सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन में 5 वर्ष का पूर्व अनुभव होना चाहिए तथा उसके साथ अथवा उसका सहयोग करने वाले आदि के पास तकनीकी सुविधा इस कार्य हेतु उपलब्ध होना चाहिए। विशेषकर ईडीकेटिड मिनरल्स की मौजूदगी पता लगाने की सुविधा।

2. ऑफरकर्ता को यह अभिकथन देना होगा कि गठित जे0 वी0 सी0 के द्वारा हवाई पूर्वेक्षण कार्य किया जाएगा।

3. ऑफरकर्ता मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम के साथ संयुक्त उपक्रम गठित कर कार्य संपादित करेगा जिसे संयुक्त उपक्रम विधिवार पी0 एल0 या आवश्यकता होने पर खनिज रियायतें प्राप्त करेगा।

4. ऑफरकर्ता की नेटपर्ध 150 करोड़ रु0 तथा उसका तीन वर्ष का वार्षिक औसत टर्नओवर रु0 300 करोड़ का होना चाहिए।

5. ऑफरकर्ता को यह सहमति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि वह राज्य खनिज निगम हो संयुक्त क्षेत्र में 11% अनसब्सक्राइब्ड अंश पूंजी देगा तथा कंपनी की अंश पूंजी का 11% हमेशा ही बना कर रखेगा।

6. ऑफरकर्ता उत्पादित हीरे पर 20/- रु0 प्रति कैरेट की दर से स्थानीय विकास हेतु सहमत होगा।

7. किसी भी ऑफरकर्ता को दो से अधिक ब्लाक आबंटित नहीं किया जाएगा।

8. ऑफर का मूल्यांकन पूर्व निर्धारित जिसमें वाणिज्यिक मापदण्डों पर किया जाएगा जिसमें वाणिज्यिक दृष्टि से ऑफरकर्ता को हीरों के विक्रय मूल्य के 10% न्यूनतम निर्धारित से अधिक कितने प्रतिशत राशि राज्य शासन को देने को सहमत हैं अपने ऑफर में उल्लेखित करना होगा। यह राशि हीरों के उत्खनन पर देय रॉयल्टी तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार को प्राप्त होने वाले कर/राजस्व के अतिरिक्त होगी।

9. ऑफरकर्ता को ऑफर के साथ 1.00 करोड़ रु0 की अमानत राशि जमा करवानी होगी।

लौह और इस्पात संबंधी संयुक्त उद्यम पैनल

2248. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे :** क्या इस्पात तथा खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय नें संयुक्त उद्यम समिति के वर्तमान स्वरूप इसकी भूमिका और उसके कार्यों के मूल्यांकन के लिए किसी विशेषज्ञ दल का गठन किया है,

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपना अन्तरिम या अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया हैं,

(ग) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में की कई सिफारिशों का ब्यौरा क्या हैं,

(घ) क्या सरकार "लौह और इस्पात संबंधी संयुक्त उद्यम पैनल" का विस्तार करने का विचार कर रही हैं, और

(ड़) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ड़) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

Losses in Visakhapatnam Steel Plant

2249. SHRI PARMESHWAR KUMAR AGARWALLA: Will the Minister of STEEL AND MINES be pleased to state:

(a) what have been the cash and overall losses in Visakhapatnam Steel Plant in 1996-97 and 1997-98;

(b) what has been its production of metallurgical coke in 1995-96, 1996-97 and 1997-98 and out of these how much have been captive consumption and outside sales during these years; and

(c) what is the impact of cheap imports of metallurgical coke of Chinese origin on its outside sale of coke, its stocks and prices?